संख्या:16/2023/24/35-4-2023/001-35-4099/119/2022

प्रेषक,

डा0संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 जनवरी,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनातर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-07/2021/28/35-4-2021 दिनांक 14 जनवरी, 2021 द्वारा सेतु निर्माण से संबंधित कार्य की लागत रू0 1938.49 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 484.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-104/2022/283/35-4-2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 484.62 लाख लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा पत्रांक: 525/त्व0आ0वि0यो0/2022-23, 23, दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में देय धनराशि रू. 484.62 लाख (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख बांसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद सिद्धार्थनगर में विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड-मिठवल में बघनी घाट में विमाहा घाट तक राप्ती नदी पर सेतु लं0 212.55 मी0, पहुंच मार्ग(दोनों तरफ 200-150 मी0) अतिरिक्त पहुंच मार्ग (दोनों तरफ 280 मी0) तथा सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	1938.49	969.24	484.62

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 2021 एवं 29 मार्च, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,84,62,000 (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख बांसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 505404101030301 सेतुओं के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:16/2023/24(1)/35-4-2023/001-35-4099/119/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
14-परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम, सेतु निर्माण इकाई, बस्ती।
15-संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in